भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1047
दिनांक 22 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए

निर्भया निधि

1047. कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन राठौर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2019-2022 के दौरान निर्भया निधि के अंतर्गत की गयी पहलें कौन सी हैं तथा संवितरित की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और पहल-वार राशि कितनी है;
(ख) क्या सरकार निर्भया निधि के अंतर्गत प्रदान किए गए कानूनी अधिकारों और सहायता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कोई संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, विशेषकर राजस्थान में जिले-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) कितने राज्यों ने महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना को कार्यान्वित किया है;
(घ) क्या सरकार ने इसे अभी तक कार्यान्वित नहीं करने वाले राज्यों के साथ बातचीत जारी रखी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) महिला हेल्पलाइन के अंतर्गत राज्य-वार तथा राजस्थान में जिला स्तर तक कितनी महिलाओं को सहायता प्रदान की जाती है; और
(च) क्या सरकार ने इस हेल्पलाइन के अंतर्गत ग्रामीण कनेक्टिविटी सुनिश्चित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : सरकार ने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने वाली पहलों/स्कीमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2013 में 'निर्भया फंड' नामक एक समर्पित कोष की स्थापना की है। निर्भया फंड की शुरुआत के बाद से इसके हिस्से के रूप में शुरू की गई पहलें और इसके तहत वितरित राशि **अनुलग्नक-**I में दी गई है। इसके अतिरिक्त, निर्भया फंड के तहत पहलों के लिए वर्ष 2019-2022 के दौरान राज्य/ संघ शासित क्षेत्र वार वितरित की गई राशि **अनुलग्नक-**II में दी गई है।
(ख) : इन पहलों में से एक 181 लघु कोड वाली 24 घंटे उपलब्ध महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) है जो आपातकालीन और गैर आपातकालीन सेवाओं के साथ ही साथ जरूरतमंद महिलाओं को महिला केन्द्रित सरकारी स्कीमों, नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराती है। सखी सेंटर के रूप में लोकप्रिय वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) देशभर में 01 अप्रैल, 2015 से क्रियाशील हैं। वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य निजी एवं सार्वजनिक स्थलों पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही जगह पर समेकित मदद और समर्थन देना और पुलिस, चिकित्सा, कानूनी सहायता और सलाह महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा के मुकाबले के लिए मनोवैज्ञानिक समर्थन जैसी तुरंत आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सेवाएं प्रदान करना है। अभी तक 758 वन स्टॉप सेंटरों का अनुमोदन किया गया है जिनमें

राजस्थान में क्रियाशील 33 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) सहित 35 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 708 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) क्रियाशील हैं। वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) और महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) की सेवाएं शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, राजस्थान के लिए वर्ष 2016-17 में 'चिरायु- ए फ्रेंड फोर एवर' नामक परियोजना अनुमोदित की गई थी जिसका लक्ष्य राजस्थान के 7 जिलों की कुल 2071 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए सामुदायिक कार्य समूह का गठन करना था।

इसके साथ ही भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए अम्ब्रेला स्कीम के रूप में एक समेकित महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम 'मिशन शक्ति' का शुभारंभ किया है। 'सामर्थ्य उप-स्कीम' के तहत महिला सशक्तिकरण हब (एचईडब्ल्यू) घटक राष्ट्रीय, राज्य/संघ शासित क्षेत्र और जिला स्तर पर जागरूकता पैदा करने, संवेदीकरण, प्रशिक्षण आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए है जिससे महिलाएं अपनी पूरी क्षमता को साकार कर सकें।

(ग) और (घ) : महिला पुलिस वॉलेंटियर(एमपीवी) स्कीम के तहत 13 राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया था। यद्दिप इस स्कीम को केवल 7 राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में क्रियाशील किया गया था। महिला पुलिस वॉलेंटियर (एमपीवी) स्कीम का तृतीय पक्ष मूल्यांकन अध्ययन नीति आयोग द्वारा किया गया था। कथित अध्ययन ने स्कीम की संस्थागत संरचना और कार्यान्वयन में कमियां पाई। तृतीय पक्ष मूल्यांकन, पूर्व के अनुभवों और राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के साथ परामर्श और मिशन शक्ति के अंतर्गत समुचित रूप से उचित प्रावधानों को शामिल करते हुए 01.04.2022 से महिला पुलिस वॉलेंटियर स्कीम को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

(ड.) और (च) : महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) में प्राप्त कॉल्स का जिलेवार ब्योरा नहीं रखा जाता। यद्दिप महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) में राज्य/संघ शासित वार पंजीकृत कॉल्स का ब्यौरा **अनुलग्नक-** III में दिया गया है।

महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) पूरी तरह राज्य सरकारों के निर्देशन, प्रबंधन और पर्यवेक्षण में कार्य करती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी संबंधी किसी प्रकार का मुद्दा केन्द्र सरकार के नोटिस में नहीं आया है।

*****

अनुलग्नक-I

'निर्भया निधि' विषय पर कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन राठौर द्वारा 22.07.2022 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1047 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

निर्भया निधि की शुरुआत के बाद से इसके भाग के रूप में शुरू की गई पहलें और उनके लिए वितरित राशि

मंत्रालय/ विभाग	क्र.सं.	परियोजना का नाम	वितरित राशि(करोड़ रुपये में)
गृह मंत्रालय		आपात प्रतिक्रिया सहयोग प्रणाली (ईआरएसएस)	364.03
		केंद्रीय पीड़ित मुआवज़ा कोष (सीवीसीएफ) का सृजन	200.00
		महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)	142.00
		सीसीपीडब्ल्यूसी के तहत उप-परियोजना	
		दिल्ली में जिला और उप-मंडलीय थाना स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं/ काउंसलरों की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव	5.01
		नानकपुरा में महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष पुलिस यूनिट (एसपीयूडब्ल्यूएसी) और पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष पुलिस यूनिट (एसपीयूएनईआर) में महिला केंद्रित सुविधाओं सहित नया भवन	20.18
		दिल्ली पुलिस की 'महिला सुरक्षा' स्कीम के तहत अन्य विभिन्न गतिविधियां	9.96
		8 शहरों यानी अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुम्बई के लिए सुरक्षित शहर प्रस्ताव	1349.58
		सीएफएसएल, चंडीगढ़ में आधुनिकतम डीएनए लैब की स्थापना	35.40
		24 राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों अर्थात दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, ओडिशा, पुद्दुचेरी, झारखंड, केरल, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात और नागालैंड में एसएफएसएल में डीएनए विश्लेषण, साइबर फॉरेंसिक और संबंधित सुविधाओं को सुदृढ़ करना	162.33
		राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में मानव दुर्व्यापार विरोधी इकाइयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण	99.86
		सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के थानों (10,000 पुलिस स्थानों को शामिल करते हुए) में महिला हेल्प डेस्कों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण	157.49
		यौन हमलों के मामलों के लिए फॉरेंसिक किटों की खरीद के लिए प्रस्ताव	29.03

		पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) के माध्यम से तीन वर्षों के लिए जांच अधिकारियों (आईओ)/अभियोजन अधिकारियों (पीओ) के लिए प्रशिक्षण का प्रस्ताव	
		वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के माध्यम से जांच अधिकारियों(आईओ) / अभियोजन अधिकारियों (पीओ) को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव	0.00
रेल मंत्रालय		समेकित आपात प्रतिक्रिया सहयोग प्रणाली (ईआरएसएस)	250.82
		कोंकण रेलवे स्टेशन पर वीडियो निगरानी प्रणाली का प्रावधान	17.64
		महिलाओं की सुरक्षा के लिए टैब खरीदने का प्रस्ताव	0.00
एमईआईटी/ आईआईटी दिल्ली		महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कारों और बसों के लिए पैनिक स्विच आधारित सुरक्षा उपकरणों का विकास और फील्ड परीक्षण	3.49
न्याय विभाग		बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत लंबित मामलों के निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना	434.31
		(वित्त वर्ष 2021-22 तक दो और वर्षों के लिए एफटीएससी का विस्तार)	0.00
पर्यटन मंत्रालय		मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन गंतव्य	6.24
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय		महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए आंध्र प्रदेश सरकार का अभय परियोजना प्रस्ताव	58.64
		यूपीएसआरटीसी, उत्तर प्रदेश सरकार में सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा	80.92
		भारी यात्री वाहनों के लिए बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम कर्नाटक सरकार द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण	33.64
		राज्य-वार वाहन ट्रैकिंग प्लेटफार्म के अनुकूलन, नियोजन और प्रबंधन के लिए सी-डैक का प्रस्ताव	192.95
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय		वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)	672.26
		महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) का सार्वभौमिकरण	74.39
		महिला पुलिस वॉलेंटियर्स (एमपीवी)	16.32
		चिराली प्रस्ताव, महिला सक्तिकरण निदेशालय	4.71
		महिलाओं और बालिकाओं के प्रति हिंसा से मुक्त स्मार्ट और सुरक्षित शहर कार्यक्रम, मध्य प्रदेश सरकार	1.04
		महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा, उत्तराखंड सरकार	0.32
		निर्भया आश्रय गृह, नागालैंड सरकार	2.55
		निर्भया डैशबोर्ड विकसित करने के लिए एनआईसीएसआई	0.24
		सूचना विभाग, एमएसएमई और निर्यात संवर्धन, यूपी सरकार का प्रस्ताव : औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए मिशन शक्ति	4.95
		बलात्कार/सामूहिक बलात्कार पीड़िताओं और गर्भवती होने वाली नाबालिग लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए संकटाकालीन देखभाल और सहायता की स्कीम	0.00
विदेश मंत्रालय		विदेशों में 10 भारतीय मिशनों में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) खोलने का प्रस्ताव	0.00

अनुलग्नक-II

'निर्भया निधि' विषय पर कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन राठौर द्वारा 22.07.2022 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1047 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

निर्भया कोष के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही पहलों के लिए वर्ष 2019-2022 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संवितरित राशि

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं..	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	वितरित राशि
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	7.59
2	आंध्र प्रदेश	28.96
3	अरुणाचल प्रदेश	21.76
4	असम	46.88
5	बिहार	84.31
6	चंडीगढ़	5.54
7	छत्तीसगढ़	41.93
8	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	8.34
9	दिल्ली	306.61
10	गोवा	9.36
11	गुजरात	136.60
12	हरियाणा	30.76
13	हिमाचल प्रदेश	22.30
14	जम्मू और कश्मीर	24.30
15	झारखंड	41.97
16	कर्नाटक	66.96
17	केरल	33.39
18	लद्दाख-यूटी	4.35
19	लक्षद्वीप	0.73
20	मध्य प्रदेश	125.78
21	महाराष्ट्र	154.25
22	मणिपुर	26.08
23	मेघालय	20.00
24	मिजोरम	22.37
25	नागालैंड	24.03
26	ओडिशा	66.10
27	पुद्दुचेरी	9.20
28	पंजाब	31.20
29	राजस्थान	84.56
30	सिक्किम	9.55
31	तमिलनाडु	127.22
32	तेलंगाना	124.75
33	त्रिपुरा	15.34
34	उत्तर प्रदेश	317.82
35	उत्तराखंड	22.82
36	पश्चिम बंगाल	29.02

*****

अनुलग्नक-III

'निर्भया निधि' विषय पर कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन राठौर द्वारा 22.07.2022 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1047 के भाग (ड.) और (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार महिला हेल्पलाइन (181) पर पंजीकृत कॉलों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल कॉल्स
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1539
2	आंध्र प्रदेश	931396
3	अरुणाचल प्रदेश	7309
4	असम	157811
5	बिहार	244803
6	चंडीगढ़	74507
7	छत्तीसगढ़	81263
8	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	528
9	दिल्ली	1121711
10	गोवा	18383
11	गुजरात	1004258
12	हरियाणा	43208
13	हिमाचल प्रदेश	4663
14	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	126457
15	झारखंड	464151
16	कर्नाटक	26184
17	केरल	113885
18	मध्य प्रदेश	194616
19	महाराष्ट्र	295424
20	मणिपुर	768
21	मेघालय	30898
22	मिजोरम	11044
23	नागालैंड	2290
24	उड़ीसा	76058
25	पंजाब	1053006
26	राजस्थान	25531
27	सिक्किम	314
28	तमिलनाडु	256412
29	तेलंगाना	89843
30	त्रिपुरा	59
31	उत्तर प्रदेश	553667
32	उत्तराखंड	5939
	कुल	**7017925**

*****